प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
08.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00 बजे

सर्वोच्च–न्यायालय आवारा कुत्ते

सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने व राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए कई दिशा–निर्देश जारी किए है। शीर्ष अदालत ने कल देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई में हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तरीके से बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण निमय, 2023 के तहत स्थानीय नगर निकायों से ऐसी जगहों से पशुओं को नियमित रूप से उठाकर आवश्यक टीकाकरण व नसबंदी के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। अन्यथा ये अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

किन्नौर पुलिस

किन्नौर जिला के नए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने
कहा है कि उनकी टीम का मुख्य फोकस नशे की रोकथाम पर रहेगा। कल कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करना रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसलिए किन्नौर पुलिस इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करेगी और किसी भी नशा तस्कर या चिट्टा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

मेरा जो अपरोच रहेगा काम करने का वो पब्लिक सेंटर होगा, सिटिजन सेंटरिंग होगा। मेरी पूरी टीम इस डारायक्शन में काम करेगी। और नशे की बजह से हमारी पीढ़ीया बर्बाद हो रही है। हम जिला किन्नौर पुलिस पूरी टीम इस विनेस को टेकल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। हिमाचल सरकार का ये बड़ा फैसला ह"कि जो भी चिटटा तस्कर है या दूसरे नशो के तस्कर है। उनको स्ट्रोगली डील किया जाए। विद एम आई एम हैंड महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जितने भी टूरिस्ट यहां आएं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके लिए बेहतर ट्रैफिक का पैसेज प्रोवाईड करना ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा।

वंदे मातरम

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के डेढ़ सौ वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा कल संगीतमय सामूहिक गान किया गया। इसमें पत्र सूचना कार्यालय और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के सभी अधिकारी, कलाकार और कर्मचारी शामिल हुए। दूरदर्शन शिमला, आकाशवाणी, केन्दीय विद्यालयों, सैन्य प्रशिक्षण कमान, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों में भी वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया।

राज्य स्तरीय उत्सव

चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में चल रहे राज्य स्तरीय कला व रंगोंत्सव में प्रदेश भर से आए प्रतिभागी विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तीन दिवसीय कला उत्सव का आज समापन होगा जिसमें लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 11 जिलों से करीब 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान जहां चम्बा के कलाकारों द्वारा पारम्परिक ऐंचली की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध किया गया वहीं अन्य राज्यों के कलाकारों ने एकल नृत्य, नाटक सहित अन्य प्रस्तुतियां दीं। राज्य स्तरीय कला व रंगोंत्सव में भाग लेने पर पहुंचे प्रतिभागियों ने खुशी जताई है ।

मेरा नाम नव्या है मैं जिला किन्नौर से बोल रही हूं हम यहां पर आए है कलां उत्सव के लिए स्टेट में यहां पर डान्स पार्टीस्पेट्स कर रही है क्लासिकल डांस में।

हम पीएम श्री सिनियर सकैंडरी स्कूल पटटा महलोग स्कूल से आएं और यहां पर पार्टीस्पेटशन में है यहां पे थ्रो स्टेलिंग जो भस्मासूर अंत है जैस शिव महाराज ने भस्मासूर को वरदान दिया पहले उन्होंने और वो उनके मारने के लिए वह उनके पीछे कैसे पड़ा और उसको मारने के लिए शिवजी महाराज ने मोहनी का रूप लिया।

मुख्यमंत्री दौरा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे मझेली पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत सरेड़ी के गांव कड़साई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे।

जीएसटी

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमी की पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंट पर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकान खरीददारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।

पेश है ये रिपोर्ट.....

अगलीपीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमीकी पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंटपर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकानखरीदारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकोंपर अब 12 प्रतिशत की जगह केवल 5 प्रतिशतजीएसटी लगेगा, जिससे फर्श और फिनिशिंग की लागत कम हो जाएगी। इसीप्रकार, रेत–चूने की ईंटों पर कर भी कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है,जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके साथ ही ईंटों के जॉब वर्कपर जीएसटी को भी 12 प्रतिशत के कर स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आवास की लागतकम हुई है और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग– एमएसएमई को समर्थन मिला है। संशोधित ढांचे के तहत यह युक्तिकरण न केवल निर्माण क्षेत्रमें एमएसएमई को मजबूत कर रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है, बल्किघरों और बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती भी बना रहा है।

.....